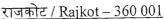


::प्रधानआयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road



Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142Email: cexappealsrajkot@gmail.com



रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

अपील / फाइलमंख्या/ Appeal /File No.

V2/26 /GDM/2018-19

मूल आदेश सं /

30/JC/2017-18

. No.

दिनांक/

Date **28-03-2018**

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-066-2019

आदेश का दिनांक /

Date of Order:

18.06.2019

जारी करने की तारीख /

19.06.2019

Date of issue:

श्री कुमार संतोष, प्रधान आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Kumar Santosh, Principal Commissioner (Appeals),Rajkot

ग अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / मेवाकर /वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजितः /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham:

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s Indian Farmer Fertilizer Co-operative Ltd. (IFFCO), Finance & Accounts Dept., Old Kandla, Dist.Kutch-370201.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीक में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क ,कन्द्रीय उत्पाद शुल्क एव सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण क प्रति अपील, कन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B क अतगत (A) एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं मेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में वताए गए अपीलों के अलावा शेष मभी अपीलें मीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (मिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, $2^{\rm nd}$ Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम में कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग व्याज की माँग और लगाया जमाना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक ते का काश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के महायक रजिस्टार के नाम में किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक द्वारट द्वारा किया जाना चाहिए। मंबंधित इाफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके माथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग,व्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना,रुगए 5 लाख या उसमें कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करीं निर्धारित शुल्क का भगतान, मंबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजस्टार के नाम से किमी भी सार्विजनक क्षेत्र के बैक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित द्वारट का मुगतान, वेंक की उस शाखा में होना चाहिए लहां मुंबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑडर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-



वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपन्न S.T.-7 में की जा सकेती एवं उसके माथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुक्क द्वारा गरित आदेश की प्रतियों सेनाम करें (उनमें से एक प्रति प्रमिणित होनी चाहिंग) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुक्क (वार्म अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदत वर्ज करने का निर्देश की प्रति मी साथ से संत्रम करती होगी। /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise (Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

सीमा शुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्त गुन सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेन्टर) के प्रति अपीलों के मामले में कन्द्रीय उत्पाद शुक्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अतर्गत संवाकर को भी वार्म की मामले प्रति कर मामले प्रति अपीलों कर से समय उत्पाद शुक्त भी कि सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर से समय उत्पाद शुक्त भी के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर से समय उत्पाद शुक्त भी के सामले के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर से समय उत्पाद शुक्त भी के तिया के अतर्गत राम शुक्त के अतर्गत राम (11) सेनवेट जमा की निर्धा के प्रति के सामले के अतर्गत राम (12) सेवाकर के अतर्गत राम (13) सेवाकर के अतर्गत स्थान के सामले के सामले हैं होगा।

(1) सेवाकर की सामले की नाम मही होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alon (i)

(ii)

भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलों में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर मचिव,
भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया
जाना चाहिए। (C) A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to subsection (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकमान के मामले में, जहां नुकमान किसी माल को किसी कारखाने में भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकमान के मामल में।

In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse whether in a factory or in a warehouse (i)

भागत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिवेट) के मामले में, जा भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र के गिया है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जा आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियंत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेपण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतिया संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3S-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी (v) ही कन्द्रीय उत्पाद शुन्क आधानयम, 1944 का बादा उठ-EB 1965 (Park 1971) / चाहिण / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

पुनरीक्षण ओवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुन्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का ममावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य स वचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाना है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथामंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुमूची-I के अनुमार मूल आदेश एवं म्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चोहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)

मीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेबाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य मंबन्धित मामलों को मिम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षिन किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने में मंबंधिन व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेवसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in. (G)

3 :: ORDER IN APPEAL ::

M/s. Indian Farmer Fertilizer Co-operative Limited, Old Kandla, Kandla Port, District – Kutch - 370201, Gujarat (hereinafter referred to as 'appellant') filed present appeal against Order-in-Original No. 30/JC/ 2017-18 dated 28.3.2018 (hereinafter referred to as "impugned order") passed by the Joint Commissioner, Central GST, Gandhidham (Kutch) (hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority"): -

- 2. The brief facts of the case are that the appellant manufactured and cleared Zinc Sulphate Monohydrate (in short ZSM) during the period from March, 2016 to May, 2016, but the clearances were not shown in ER-1 returns and they also did not pay central excise duty on the said product though department contended that central excise duty @ 6% was made applicable vide Notification No. 12/2012-CE dated 17.3.2012, as amended vide Notification No. 12/2016-CE dated 1.3.2016. Show Cause Notice No. V.31/AR-I/Div.GIM/Jt. Commr. /1/2017-18 dated 6.4.2017 was issued to the appellant demanding central excise duty of Rs. 1,01,85,655/- under Section 11A of the Central Excise Act, 1944 (hereinafter referred to as "the Act") along with interest under Section 11AA of the Act and to impose penalty under Rule 25 of Central Excise Rules, 2002 read with Section 11AC of the Act. The lower adjudicating authority vide the impugned order confirmed demand of central excise duty of Rs. 60,34,255/- for the period from 6.4.2016 to 31.5.2016 in terms of CBEC Circular No. 1022/10/2016-CX. dated 6.4.2016 along with interest and imposed penalty of Rs. 60,34,255/under Section 11AC of the Act read with Rule 25 of Central Excise Rules, 2002.
- 3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant preferred this appeal, *inter-alia*, on the following grounds: -
- (i) The impugned order has travelled beyond the scope of Show Cause Notice inasmuch as there is no allegation in the SCN that Zinc Sulphate Monohydrate manufactured by the appellant is not agricultural grade. There is no averment in SCN that Sl.No. 103 of Notification No. 12/2012-CE dated 17.3.2012 is available to Zinc Sulphate Heptahydrate and not to Zinc



gamo -

Page 3 of 7

Sulphate Monohydrate as held by the lower adjudicating authority. The SCN never proposed to deny benefit of Sl.No. 103 of Notification No. 12/2012-CE dated 17.3.2012 to Zinc Sulphate Monohydrate on the ground that exemption is available only to Zinc Sulphate Heptahydrate. Therefore, the impugned order is not tenable in the eyes of law and liable to be quashed.

- (ii) The distinction made by the lower adjudicating authority between Zinc Sulphate Monohydrate and Zinc Sulphate Heptahydrate is beyond the scope of SCN. The appellant was never put to notice about such distinction. The appellant was also not put to notice that benefit of Sl.No. 103 of Notification No. 12/2012-CE dated 17.3.2012 is available to Zinc Sulphate Heptahydrate and not to Zinc Sulphate Monohydrate. The criteria devised by the lower adjudicating authority to distinguish between Zinc Sulphate Monohydrate and Zinc Sulphate Heptahydrate is not prescribed in Notification No. 12/2012-CE dated 17.3.2012 and demand was confirmed without authority of law.
- (iii) Without prejudice, the appellant submitted that Zinc Sulphate Monohydrate manufactured by the appellant is of agriculture grade and is used as Micronutrient and hence, the same is covered by Sl.No. 103 of Notification No. 12/2012-CE dated 17.3.2012 and hence, the impugned order is legally not sustainable.
- (iv) The demand of central excise duty is not tenable and hence, neither central excise duty nor interest under Section 11AA of the Act is payable by them and penalty imposed under Section 11AC of the Act read with Rule 25 of Central Excise Rules, 2002 is not required.
- 4. Personal hearing in the matter was attended by Shri Vikas Mehta, Consultant, who reiterated the grounds of appeal and stated that they manufacture Agriculture Grade Zinc Sulphate ordinarily used as Micronutrients and hence, they are specifically covered under Sl.No. 103 of Notification No. 12/2012-CE; that Sl.No. 109A talks of many manufactured products and many products are covered and hence, it is very general; that specific entry should be allowed over general description; that the grounds



stated in the impugned order to deny benefit of exemption have not been alleged/stated in SCN and hence, the impugned order has travelled beyond the scope of SCN, which is neither legal nor proper; that their appeal should be allowed in view of above and the fact that the product in question is agricultural grade and hence, exempted.

4.1 In additional written submissions, it is submitted that as per SCN (para 3, page 2) zinc content of goods manufactured by appellant is minimum 33%, however, the impugned order at Para 9.1 has found that Zinc Sulphate Monohydrate is having zinc content above 35%; that SCN did not cite any test report and hence, such findings cannot be delivered without citing any test report that the impugned order has travelled beyond the scope of SCN also for the reason that there is no allegation that goods manufactured by appellant is not agriculture grade and only Zinc Sulphate Heptahydrate can be treated as agriculture grade; that SCN makes no reference to Zinc Sulphate Heptahydrate and no comparison is proposed in SCN; that the appellant submitted analysis report of Zinc Sulphate Monohydrate certifying that it is agriculture grade free flowing material conforming to IS: 15848:2009.

FINDINGS:

- 5. I find that the appellant has deposited 7.5% of demand confirmed vide Challan dated 26.5.2018 as stated by them in their Appeal Memorandum in compliance to Section 35F (4) of the Act.
- 6. I have carefully gone through the records of the appeal, the impugned order, the grounds of appeal and the submissions made by the appellant including during and after personal hearing. The issue to be decided in the present appeal is as to whether the impugned order confirming demand of central excise duty on Zinc Sulphate Monohydrate manufactured and cleared by appellant and imposing penalty is correct or not.
- 7. The appellant has strongly contended that the impugned order has travelled beyond the scope of Show Cause Notice since there is no allegation in the SCN that Zinc Sulphate Monohydrate manufactured by the appellant is not agricultural grade; that they manufacture Agriculture Grade

& m

Page 5 of 7

Zinc Sulphate ordinarily used as Micronutrients and hence, they are specifically covered under Sl.No. 103 of Notification No. 12/2012-CE whereas, the impugned order held that Zinc Sulphate Monohydrate manufactured by the appellant attracted concessional rate of central excise duty @ 6% under Sl.No. 109A of Notification No. 12/2012-CE dated 17.3.2012 as amended vide Notification No. 12/2016-CE dated 1.3.2016. I would like to re-produce Sl.No. 103 and Sl.No. 109A of Notification No. 12/2012-CE dated 1.3.2012, as amended, which read as under: -

TABLE

SI. No.	Chapter or heading or sub- heading or tariff item of the First Schedule	Description of excisable goods	Rate	Condition No.
(1)	. (2)	(3)	(4)	(5)
103	2833 29	Agricultural grade zinc sulphate ordinarily used as micronutrient	Nil	
				_
				-
109A	28, 29 or 38	Micronutrients, which are covered under serial number 1(f) of Schedule 1, Part (A) of the Fertilizer Control Order, 1985 and are manufactured by the manufacturers which are registered under the Fertilizer Control Order, 1985	6%	-

7.1 Thus, SI.No. 103 of the said Notification specifies nil rate of duty for goods described as Agricultural grade Zinc Sulphate ordinarily used as micronutrient whereas SI.No. 109A of the said Notification inserted vide Notification No. 12/2016-CE dated 1.3.2016 specifies central excise duty at the rate of 6% on Micronutrients covered under serial number 1(f) of Schedule 1, Part (A) of the Fertilizer Control Order, 1985 and are manufactured by the manufacturers which are registered under the Fertilizer Control Order, 1985. I find that the department has neither challenged classification of the goods manufactured by the appellant nor disputed that Zinc Sulphate Monohydrate manufactured by the appellant is not of agricultural grade. The exemption from payment of central excise duty granted to agricultural grade Zinc Sulphate ordinarily used as Micronutrient has been granted under SI.No. 103 of Notification No.

parmo

12/2012-CE dated 17.3.2012, since issuance of the said notification and has not been withdrawn even after insertion of SI.No. 109A vide Notification No. 12/2016-CE dated 1.3.2016. Hence, I am of the considered view that the appellant is eligible for exemption from payment of central excise duty and therefore, the demand of central excise duty is legally unsustainable and benefit of exemption from payment of central excise duty under Sl.No. 103 of Notification No. 12/2012-CE dated 17.3.2012 cannot be denied to the appellant. It is settled legal position that that when exemption there are two entries in the notification. manufacturer/importer is entitled to the benefit of exemption as held by the Hon'ble Supreme Court in the cases of HCL Limited v. Collector of Customs, New Delhi - 2001 (130) E.L.T. 405 (S.C.) and Share Medical Care v. Union of India - 2007 (209) E.L.T. 321 (S.C.). Hence, I set aside the impugned order confirming demand of central excise duty. Since demand is not sustainable, the appellant is not liable to pay interest and no penalty under Section 11AC of the Act is imposable on the appellant.

- 8. In view of above, I set aside the impugned order and allow the appeal.
- ९. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 9. The appeal filed by the appellant is disposed off in above terms.

Figiting

कुमार संतोष) प्रधान आयक्त (अपील्स)

By Speed Post

To

M/s. Indian Farmer Fertilizer Co-operative Limited,

Old Kandla,

Kandla Port,

District - Kutch - 370201, Gujarat

मेसर्स इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र्स को-ओपरेटिव लिमिटेड,

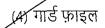
ओल्ड कांडला,

कांडला पोर्ट.

डिस्ट्रिक्ट – कत्छ – ३७०२०१ गुजरात

प्रति:

- .. (1) प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर, अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु ।
- (2) आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (3) सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर मण्डल, अंजार-भचाउ को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।





Page 7 of 7

			O
	·		O